दृष्टि
The Vision

करेंट अफेयर्स हरियाणा

जनवरी (संग्रह)

2022

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

हरियाणा **5**

- 15.40 लाख किशोरों को टीकाकरण प्रारंभ 5
- हरियाणा के गुरुग्राम में बनाया जाएगा हेलीहब 5
- हरियाणा में 'पदमा' स्कीम के लिये 'लैंड-पूल पॉलिसी' निर्मित करने के निर्देश 6
- राज्य में ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिये पाँच 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' खोले जाएंगे 6
- सोलर पंप लगाने में हरियाणा अग्रणी राज्य 6
- हरियाणा में बेरोज़गारी दर 6.1 प्रतिशत 7
- इंडिया स्किल-2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता 7
- ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर बनेंगे दस रेलवे स्टेशन 8

नोट :

- यूनाइटेड किंगडम और हरियाणा ने सहयोग के लिये एफओई पर हस्ताक्षर किये 8
- हरियाणा में एस्मा कानून लागू 9
- 52 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेताओं को खेल विभाग में मिलेगी नौकरी 9
- दीक्षा डागर, यश घणघस टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल 9
- ब्रिगेडियर लखविंदर के आश्रितों को मिलेगी 50 लाख रुपए की सहायता राशि 10
- हरियाणा में 75% नौकरी आरक्षण कानून लागू 10
- रेनू भाटिया बनीं राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष 11
- हरियाणा ने कक्षा V, VIII के लिये बोर्ड परीक्षा आयोजित करने हेतु 'नो डिटेंशन पॉलिसी' को रद्द कर दिया 11
- हरियाणा में स्टार्टअप्स को 75% आरक्षण कानून से छूट 12
- हरियाणा, हिमाचल सरकार ने बांध निर्माण के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये 12
- इंडियन ऑयल एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल और ग्रीन कॉम्बो लुब्रिकेंट का भारत में पहला ट्रॉयल हरियाणा से हुआ शुरू 13

नोट :

- राज्य सूचना आयोग के भवन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर होगा 14
- हरियाणा में हर साल एक हज़ार युवाओं को दिया जाएगा साहसिक-खेल प्रशिक्षण 14
- हरियाणा के 2 बच्चे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित 15
- हरियाणा के 5 व्यक्ति पद्म पुरस्कारों के लिये चयनित 15
- हरियाणा पुलिस के 14 अधिकारी पुलिस पदक से अलंकृत 16
- गुरुग्राम में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन 16
- उन्नति ने जीता ओडिशा ओपन 17

नोट :

हरियाणा

15.40 लाख किशोरों को टीकाकरण प्रारंभ

चर्चा में क्यों ?

- हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि हरियाणा में 3 जनवरी से 15 से 18 आयु वर्ग के 15.40 लाख किशोरों को कोरोनारोधी वैक्सीन प्रारम्भ की गई है।

प्रमुख बिंदु

- स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि हरियाणा में 98 प्रतिशत पहली और 70 प्रतिशत दूसरी डोज लगाई जा चुकी हैं। अभी 8 लाख से ज़्यादा कोवाक्सीन और 31 लाख से ज्यादा कोविशील्ड उपलब्ध हैं।
- स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिये प्रदेश सरकार तैयार है। पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर हैं। 84 सरकारी अस्पतालों में पीएसए प्लांट चालू हो चुके हैं। 54 प्राइवेट अस्पतालो में भी प्लांट लगा चुके हैं।
- शेष अस्पतालों में भी जल्द यह प्लांट लगाने का प्रयास किया जा रहा है। एक जनवरी से सार्वजनिक स्थानों पर दोनों खुराक नहीं लेने वालों पर प्रतिबंध के फैसले से टीकाकरण बढ़ा है।

हरियाणा के गुरुग्राम में बनाया जाएगा हेलीहब

चर्चा में क्यों ?

- 4 जनवरी, 2022 को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपने कार्यालय में नागरिक उडन्यन विभाग, एचएसआईआईडीसी, टाउन एंड कंट्री प्लांनिंग समेत अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि गुरुग्राम में हेलीहब बनाया जाएगा, जहाँ पर हेलीकॉप्टरों के लिये हेलीपोर्ट से लेकर उनके हैंगर, रिपेयर समेत अनेक एविएशन फेसिलिटी उपलब्ध होंगी।

प्रमुख बिंदु

- यह हेलीहब देश में अपनी तरह का ऐसा पहला हब होगा, जहाँ पर हेलीकॉप्टरों के लिये एक ही स्थान पर उक्त सारी सुविधाएँ होंगी।
- उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास नागरिक उडन्यन विभाग का प्रभार भी है, ने बताया कि गुरूग्राम में जिस स्थान पर हेलीहब बनाया जाएगा, वहाँ से मैट्रो की सुविधा भी नज़दीक होगी और नोएडा, भिवानी आदि औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ाव भी सहज होगा।
- उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि उक्त प्रस्तावित हेलीहब के संबंध में विस्तार से प्रोजेक्ट तैयार करें और ज़मीन लेने व अन्य सुविधाओं को शुरु करने में आने वाली अड़चनों को दूर कर कार्य आरंभ करें।
- विदित हो कि दुष्यंत चौटाला के प्रयासों से राज्य में नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा कई महत्त्वपूर्ण परियोजनाएँ शुरू की गई हैं और पहले से चालू परियोजनाओं में तेज़ी लाई जा रही है।
- हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा को विस्तार से तैयार करने व डिफेंस से संबंधित अन्य परियोजनाएँ आरंभ करने पर तेज़ी से कार्य किया जा रहा है।
- एयरपोर्ट के आस-पास बने शेड को हटाने, हवाई अडन्न परिसर में नए हैंगर व एप्रोन बनाने, धांसू रोड पर रनवे के निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन साइट पर बिजली पोल व लाइन हटाने, 33 किलोवाट के सब स्टेशन की स्थापना, ऑब्जरवेशन होम को ढहाने, टर्मिनल तथा अन्य भवन निर्माण को समय पर पूरा करने के निर्देश दिये गए हैं।
- हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नागरिक उडन्यन विभाग के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि वे भिवानी, नारनौल तथा पिंजोर हवाई पटी के आस-पास अतिरिक्त ज़मीन तलाशें, ताकि एविएशन से संबंधित अन्य गतिविधियों को विस्तार रूप दिया जा सके।

नोट :

हरियाणा में 'पदमा' स्कीम के लिये 'लैंड-पूल पॉलिसी' निर्मित करने के निर्देश

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 'पदमा' स्कीम से संबंधित अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिये कि 'पदमा' स्कीम के लिये ऐसी 'लैंड-पूल पॉलिसी' निर्मित की जाए, जिससे ज़मीन के मालिक ग्रामीण लोगों को अधिक-से-अधिक फायदा हो और गाँव में रोज़गार के अवसर बढ़ें।

प्रमुख बिंदु

- उप-मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद जानकारी दी कि केंद्र की 'पदमा' स्कीम को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार इस पर तेजी से काम करने जा रही है। प्रदेश में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिये लैंड पूलिंग के तहत प्रत्येक ब्लॉक में करीब पचास एकड़ ज़मीन जुटाई जाएगी।
- उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ब्लॉक-वाइज कुछ उत्पाद तय किये गए हैं, जिनको एक्सपोर्ट करवाने में भी सरकार मदद करेगी। राज्य के कई गाँवों में हुनरमंद लोगों द्वारा ऐसे गुणवत्तापरक प्रोडक्ट तैयार किये जाते हैं, जिनकी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी कीमत मिल सकती है, लेकिन जानकारी के अभाव में उनको मजबूरी में लोकल लेवल पर कम दामों पर बेचना पड़ता है।
- उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के मुताबिक राज्य सरकार की मंशा है कि प्रत्येक ब्लॉक में उस ब्लॉक के लोगों द्वारा उत्पादित बेहतरीन प्रोडक्ट के लिये एक क्लस्टर बनाया जाए, जहाँ पर एमएसएमई की भाँति लोगों को उद्योग लगाने के लिये प्लॉट उपलब्ध करवाए जा सकें। इस क्लस्टर में बिजली, पानी, सड़क, बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर जैसी सुविधाएँ मुहैया करवाई जाएंगी।

राज्य में ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिये पाँच 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' खोले जाएंगे

चर्चा में क्यों?

- 6 जनवरी, 2022 को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य में में ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिये पाँच 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' खोले जाएंगे। इनके अलावा, 20 आईटीआई या बहुतकनीकी संस्थानों में भी रिसर्च सेंटर आरंभ किये जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रत्येक 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' को 5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसी प्रकार 20 आईटीआई या बहुतकनीकी संस्थानों को 25-25 लाख रुपए की वित्तीय मदद की जाएगी।
- उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दोपहिया, तिपहिया तथा चारपहिया ई-व्हीकल्स को प्रोत्साहित करने पर बल दे रही है। राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 'ई-व्हीकल' खरीदने पर विशेष रियायत दी जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा ई-व्हीकल निर्माता कंपनियों, प्रयोग करने वाले वाहन चालकों तथा चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाले लोगों को फोकस करके 'हरियाणा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी' बनाई जा रही है जिसमें उनको विशेष छूट दी जाएंगी।
- प्रदेश सरकार की योजना है कि वर्ष 2022 में राज्य में ई-व्हीकलों की भारी तादाद हो। प्रदेश सरकार का यह भी प्रयास है कि ई-व्हीकल के लिये बनाई जा रही प्रदेश की 'हरियाणा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी' पूरे देश में सर्वोत्कृष्ट हो।

सोलर पंप लगाने में हरियाणा अग्रणी राज्य

चर्चा में क्यों?

- 6 जनवरी, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के तहत सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिये सौर जल पंपों की स्थापना के मामले में राज्य देश में अग्रणी है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने ये बात वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित डिजिटल उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान किसानों को सोलर पंप प्रदान करने के दौरान कही।

- इस अवसर पर खट्टर ने सौर जल पंपिंग कार्यक्रम की एक पुस्तिका और किसानों के लिये एक उपयोगिता पुस्तिका का भी विमोचन किया।
- मुख्यमंत्री ने राज्य में 50 एचपी से कम के नलकूप, जो बिजली से चल रहे हैं और कृषि कार्यों के लिये उपयोग किये जा रहे हैं, उन्हें सौर ऊर्जा में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।
- खट्टर ने उपायुक्तों को सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने और राज्य सरकार की 'हर खेत को पानी' योजना के तहत हर खेत तक पानी पहुँचाने के लिये एक विशेष अभियान शुरू करने का भी निर्देश दिया।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पिछले सात वर्षों में 25897 सोलर पंप सेट लगाए गए हैं और इस वर्ष 13800 पंप सेट लगाने का कार्य प्रगति पर है। हरियाणा गुजरात के बाद देश का दूसरा राज्य है, जिसने सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया है।
- उन्होंने कहा कि सरकार इन सोलर पंपों पर 75 फीसदी सब्सिडी दे रही है।
- उन्होंने कहा कि 'म्हारा गाँव जगमग गाँव' योजना के तहत प्रदेश के 5500 गाँवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति संभव हो गई है, साथ ही लाइन लॉस 33 से घटकर 14 प्रतिशत हो गया है।

हरियाणा में बेरोज़गारी दर 6.1 प्रतिशत

चर्चा में क्यों?

- 7 जनवरी, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य में बेरोज़गारी दर 6.1 प्रतिशत है, जिसमें 18-58 वर्ष की आयु के लगभग 10.59 लाख लोगों ने खुद को बेरोज़गार घोषित किया है।

प्रमुख बिंदु

- परिवार पहचान-पत्र (पीपीपी) कार्यक्रम के तहत एकत्र किये गए आँकड़ों के अनुसार (जिसने अब तक राज्य के 98 प्रतिशत परिवारों को कवर किया है) 18-58 वर्ष के आयु वर्ग के 1.73 करोड़ लोग हैं, जिनमें से 1059530 लोगों ने खुद को बेरोज़गार घोषित किया है। इन आंकड़ों के आधार पर हरियाणा की बेरोज़गारी दर महज़ 6.1 फीसदी है।
- मुख्यमंत्री ने राज्य को बदनाम करने के लिये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए कहा कि देश में हरियाणा में उच्चतम बेरोज़गारी दर पर (सीएमआईई) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कॉन्ग्रेस नेताओं द्वारा की जा रही बयानबाज़ी झूठी और निराधार है।
- पिछली रिपोर्ट में सीएमआईई ने हरियाणा की बेरोज़गारी दर 35.1 प्रतिशत आँकी थी। सीएमआईई की नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि हरियाणा ने दिसंबर 2021 में देश में सबसे अधिक बेरोज़गारी दर 34.1 प्रतिशत दर्ज की, जबकि भारत में 7.9 प्रतिशत की बेरोज़गारी दर दर्ज की गई है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक कुल 6578311 परिवारों को पीपीपी के तहत पंजीकृत किया गया है और पंजीकृत जनसंख्या का आँकड़ा 25799000 है। इनमें लगभग 18 लाख बच्चे हैं।
- उल्लेखनीय है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) ने भारत में बेरोज़गारी दर 9.4 प्रतिशत दिखाई है, जबकि हरियाणा में यह जनवरी-मार्च 2021 के दौरान 10.3 प्रतिशत थी, लेकिन उसी अवधि में सीएमआईई ने देश में बेरोज़गारी दर 7.4 प्रतिशत, जबकि हरियाणा में 29.3 प्रतिशत बेरोज़गारी दिखाई है।

इंडिया स्किल-2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता

चर्चा में क्यों?

- 10 जनवरी, 2022 को नई दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी इंडिया स्किल-2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। इसमें हरियाणा की टीम के खिलाड़ियों को 11 पदक मिला।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- स्थानीय अधिकारियों और राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत 7 से 9 जनवरी तक प्रगति मैदान सहित कई स्थानों पर प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई। वहीं 3 से 5 जनवरी तक बेंगलुरु और मुंबई में आठ कौशल प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई।
- विदित हो कि चीन में होने वाली आगामी विश्व कौशल प्रतियोगिता-2022 में हरियाणा देश का प्रतिनिधित्व करेगा।
- हरियाणा की टीम को तीन स्वर्ण, चार रजत, एक काँस्य पदक के साथ 3 उत्कृष्टता पदक प्राप्त हुआ। हरियाणा के सोनू लाठेर ने ऑटो बॉडी रिपेयर में, अनुराज ने आरएंडएसी में और मनीष कुमार ने वेल्डिंग श्रेणी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया।
- कुकिंग में कैशव कौंडल, इंडस्ट्री डिजाइन में देविका झुनझुनवाला और मेक्ट्रोनिक्स श्रेणी में अभय व वियापू नागार्जुन ने रजत पदक जीता है। रेस्टोरेंट सेवाओं में जगत यादव को काँस्य पदक मिला है।
- आरएंडएसी में आकाश, ब्यूटी थेरेपी में समरपिका व इंडस्ट्रियल कंट्रोल श्रेणी में अखिलेश कुमार ने उत्कृष्टता पदक हासिल किये हैं।
- उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के युवाओं का शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास करने के उद्देश्य से दुधोला, पलवल में देश की पहली विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित की है। इसमें युवाओं को विभिन्न प्रकार के कौशल प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं।
- गौरतलब है कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC), कौशल विकास और मंत्रालय के निर्देशन में प्रति दो वर्ष में भारत कौशल प्रतियोगिताओं का नेतृत्व और आयोजन करता है। विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के कुशल युवा अपने-अपने कौशल में प्रतिस्पर्धा करते हैं।

ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर बनेंगे दस रेलवे स्टेशन

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटेर ने जानकारी दी कि हरियाणा से गुज़रने वाले ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर व वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर 10 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- इसके अलावा, हिसार एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी सुगम हो, इसके लिये दिल्ली से हिसार तक क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली (रिजॉर्ट रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) रेल मार्ग विकसित किये जाने का केंद्र को प्रस्ताव दिया गया है।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि रोहतक की एलिवेटिड रेलवे लाइन के नीचे सड़क मार्ग विकसित किये जाने के लिये रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दी गई है। कैथल की एलिवेटिड रेलवे लाइन परियोजना के लिये भी डीपीआर बनाकर शीघ्र स्वीकृति रेल मंत्रालय द्वारा प्रदान कर दी जाएगी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि पलवल-पृथला तक फ्रेट कॉरिडोर के शेष बचे हुए लिंक के निर्माण के लिये विभाग को जल्द-से- जल्द ज़मीन अधिग्रहण करने हेतु निर्देश दे दिये जाएंगे। इस लिंक के बनने से इस क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को बहुत लाभ होगा।

यूनाइटेड किंगडम और हरियाणा ने सहयोग के लिये एफओई पर हस्ताक्षर किये

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटेर के आवास पर यूनाइटेड किंगडम और हरियाणा के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिये एक फ्रेमवर्क ऑफ एंगेजमेंट (एफओई) पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- इस एफओई पर कैरोलीन रोवेट, ब्रिटिश उप उच्चायुक्त, चंडीगढ़ और योगेंद्र चौधरी, प्रधान सचिव, विदेश सहयोग विभाग, हरियाणा ने हस्ताक्षर किये।
- इस अवसर पर रोवेट ने कहा कि एफओई में कार्य के व्यापक क्षेत्र शामिल हैं, जो यूके और हरियाणा के बीच सहयोग बनाने में मदद करेंगे।
- उन्होंने कहा कि यूके और हरियाणा राज्य के बीच एंगेजमेंट की रूपरेखा पर हस्ताक्षर एक मज़बूत आधार प्रदान करता है, जिस पर दोनों पक्ष अपने भविष्य के सहयोग का निर्माण कर सकते हैं।
- कैरोलीन रोवेट ने कहा कि स्वच्छ विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में साझेदारी दोनों देशों के लिये प्राथमिकता हैं।

हरियाणा में एस्मा कानून लागू

चर्चा में क्यों?

- 11 जनवरी, 2022 को हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि कोरोना की भयावह स्थिति के दौरान डॉक्टर्स की हड़ताल को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। अब 6 महीने तक स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल नहीं कर सकेंगे।

प्रमुख बिंदु

- स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन की 14 जनवरी की संभावित हड़ताल की चेतावनी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने एस्मा (आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम) लागू कर दिया है।
- एस्मा की अधिसूचना के अनुसार स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा की विभिन्न संस्थाओं, जैसे- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, आयुष में संविदा, दैनिक मज़दूरी, मानदेय इत्यादि पर नियोजित व्यक्तियों सहित कार्यरत् डॉक्टरों या अन्य श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करना प्रतिबंधित है।
- हरियाणा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1974 (1974 का 40) की धारा 4-क की उपधारा (1) के तहत यह आदेश जारी किये गए हैं।

---

52 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेताओं को खेल विभाग में मिलेगी नौकरी

चर्चा में क्यों?

- 12 जनवरी, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटेर ने घोषणा की कि राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 52 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेताओं को खेल विभाग में रोज़गार दिया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि युवाओं को कमल क्लबों से जोड़ा जाएगा, जो 10,000 से अधिक की आबादी वाले 125 गाँवों में बनेंगे।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने यह घोषणा भारत विकास परिषद, हांसी द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती पर डिजिटल रूप से आयोजित रक्तदान शिविर में की।
- उन्होंने कहा कि कमल क्लब में अधिक-से-अधिक युवाओं को जोड़ा जाएगा। पहले 10,000 की आबादी वाले गाँवों पर विचार किया जाएगा, उसके बाद 8,000 की आबादी वाले गाँवों और फिर धीरे-धीरे कम आबादी वाले गाँवों में यह क्लब स्थापित किया जाएगा।
- इस क्लब का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को खेल और अन्य सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना है, ताकि उनकी क्षमता, बुद्धि और शक्ति को बढ़ाया जा सके, जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी।
- स्वेच्छा से काम करने के इच्छुक युवाओं के लिये समर्पण पोर्टल बनाया गया है। अब तक यहाँ 1300 युवाओं ने पंजीकरण कराया है। युवाओं को सामाजिक कार्यों में शामिल किया जाएगा, ताकि वे समाज सेवा के प्रति संवेदनशील होने के साथ-साथ इस तरह की गतिविधियों में शामिल होने के लिये प्रेरित हों।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार न केवल देश में, बल्कि विदेशों में भी युवाओं को अवसर प्रदान करने के लिये काम कर रही है। कॉलेज से पास होने वाले युवाओं के लिये निःशुल्क पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं, ताकि वे शिक्षा और रोज़गार के लिये विदेश जा सकें।
- राज्य सरकार युवाओं को नए स्टार्टअप शुरू करने के अवसर भी प्रदान कर रही है, ताकि उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके और नए रोज़गार सृजित किये जा सकें।

दीक्षा डागर, यश घणघस टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा हरियाणा की गोल्फर दीक्षा डागर और जुडोका यश घणघस को क्रमशः कोर एवं डेवलपमेंट ग्रुप में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) में शामिल किया गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- 21 वर्षीया बायें हाथ की खिलाड़ी दीक्षा डागर हरियाणा के झज्जर की रहने वाली हैं। डागर 2017 ग्रीष्मकालीन डिफ्लिम्पिक्स में रजत पदक विजेता हैं और पिछले साल ओलंपिक खेलों में 50वें स्थान पर रहीं।
- केंद्रीय खेल मंत्रालय मुख्य रूप से प्रत्येक राष्ट्रीय खेल महासंघ के प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता के वार्षिक कैलेंडर (एसीटीसी) के तहत उत्कृष्ट एथलीटों का समर्थन करता है।
- टीओपीएस उन क्षेत्रों में एथलीटों को सहायता प्रदान करता है, जो एसीटीसी के अंतर्गत नहीं आते हैं तथा एथलीटों की अप्रत्याशित ज़रूरतों को पूरा करते हैं, क्योंकि वे ओलंपिक एवं पैरालंपिक खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने की तैयारी करते हैं।
- वहीं खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल (एमओसी) ने पहलवानों- बजरंग पुनिया तथा सुनील कुमार को विदेशी प्रदर्शन प्रशिक्षण के लिये वित्तीय सहायता को मंज़ूरी दे दी है।

ब्रिगेडियर लखविंदर के आश्रितों को मिलेगी 50 लाख रुपए की सहायता राशि

चर्चा में क्यों?

- 14 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटेर ने कहा कि तमिलनाडु हेलिकॉप्टर क्रैश हादसे में जान गँवाने वाले हरियाणा के ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिडन्र के परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता राशि देने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके साथ-साथ ब्रिगेडियर के परिवार से किसी एक आश्रित को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिक और अर्धसैनिक बल की एक्सग्रेसिया पॉलिसी के तहत शहीद होने वाले सैनिक परिवार के आश्रितों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ सरकारी नौकरी दिये जाने का प्रावधान है।
- इस नीति के तहत हेलिकॉप्टर क्रैश हादसे में जान गँवाने वाले ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह की मौत को प्रोविजनल लड़ाई दुर्घटना मानते हुए विशेष आर्थिक सहायता व नौकरी देने की घोषणा की गई है। इस तरह का यह हरियाणा में पहला मामला है।
- उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु के कुन्नूर ज़िले में 8 दिसंबर को सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिडन्र समेत सेना के कई जवानों ने हेलीकॉप्टर हादसे में जान गँवा दी थी।

हरियाणा में 75% नौकरी आरक्षण कानून लागू

चर्चा में क्यों?

- 16 जनवरी, 2022 को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य में 75 प्रतिशत नौकरी आरक्षण कानून 15 जनवरी से लागू कर दिया गया है। प्रदेश में स्थापित सभी निजी क्षेत्र की कंपनियों, संस्थानों, ट्रस्टों, सोसाइटियों और उद्योगों में नौकरियों के लिये अब राज्य के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- इस व्यवस्था के लागू होने से प्रदेश के लाखों युवाओं के लिये निजी क्षेत्र में रोज़गार के नए रास्ते खुलेंगे।
- इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर के साथ एक समर्पित पोर्टल भी बनाया गया है। कंपनियों को पोर्टल पर अपनी रिक्ति दर्शानी होगी, जिस पर सरकार लगातार नज़र रखेगी।
- 'हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोज़गार अधिनियम, 2020', जो स्थानीय युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है, निजी क्षेत्र की कंपनियों, समितियों, ट्रस्टों, सीमित देयता भागीदारी फर्मों, साझेदारी फर्मों और 10 या अधिक व्यक्तियों को रोज़गार देने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है, जो राज्य में निर्माण, व्यवसाय करने या कोई सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से वेतन, मज़दूरी या अन्य पारिश्रमिक का भुगतान करते हैं।

- इन सभी नियोक्ताओं के लिये अब यह अनिवार्य है कि वे अपने सभी कर्मचारियों को नामित एचयूएम पोर्टल पर सकल मासिक वेतन या पारिश्रमिक 30,000 रुपए से अधिक न दें।
- राज्य सरकार द्वारा जारी हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोज़गार नियम, 2021 ने राज्य में निजी नियोक्ताओं के लिये 75 प्रतिशत आरक्षण कानून के अनुपालन के संबंध में एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है।
- स्थानीय उम्मीदवारों की शिकायतों के निवारण और कानून के तहत नियोक्ताओं को छूट प्रदान करने के लिये राज्य सरकार को अधिकृत अधिकारियों हेतु नियमों में समय-सीमा भी निर्धारित की गई है।

रेनू भाटिया बनीं राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष

चर्चा में क्यों?

- 17 जनवरी, 2022 को हरियाणा सरकार ने एनआईटी फरीदाबाद की रेनू भाटिया को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति तीन वर्ष के लिये हुई है।

प्रमुख बिंदु

- महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रधान सचिव जी. अनुपमा ने उनकी नियुक्ति का आदेश जारी किया। इस नियुक्ति के साथ ही एक साल से खाली चला आ रहा महिला आयोग अध्यक्ष का पद भर गया है।
- इससे पहले महिला आयोग की अध्यक्ष का कार्यभार आयोग की उपाध्यक्ष प्रीति भारद्वाज संभाल रही थीं। प्रीति भारद्वाज को पुन: राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है तथा उनका कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया है। दोनों ही पदों पर नियुक्ति के नियम व शर्तें बाद में जारी की जाएंगी।
- रेनू भाटिया भाजपा नेत्री एवं फरीदाबाद निवासी हैं। वो काफी लंबे समय से भाजपा में सक्रिय हैं और वह फरीदाबाद नगर निगम की डिप्टी मेयर भी रह चुकी हैं।
- राज्य आयोग की पूर्व अध्यक्ष प्रतिभा सुमन के बाद प्रीति भारद्वाज ने ही कार्यकारी अध्यक्ष का ज़िम्मा संभाला था। उन्होंने अनेक मामलों में स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की, जिसमें विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के प्रदर्शनों में महिला अधिकारों के हनन का मामला भी शामिल रहा।

हरियाणा ने कक्षा V, VIII के लिये बोर्ड परीक्षा आयोजित करने हेतु 'नो डिटेंशन पॉलिसी' को रद्द कर दिया

चर्चा में क्यों?

- 18 जनवरी, 2022 को हरियाणा सरकार ने 'नो डिटेंशन पॉलिसी' को खत्म करने और दो कक्षाओं में बोर्ड परीक्षा शुरू करने के लिये हरियाणा बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम, 2011 में संशोधन करने हेतु अधिसूचना जारी की।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2022 नामक नए नियमों के तहत, राज्य अब कक्षा v और VIII के अंत में एक नियमित परीक्षा आयोजित करेगा। कक्षा v और VIII में बोर्ड परीक्षा इसी शैक्षणिक वर्ष से शुरू की जाएगी।
- इस परीक्षा में फेल होने वाले छात्र और पुन: परीक्षा में भी असफल छात्र को वापस उसी कक्षा में रखा जाएगा।
- आरटीई 2009 के तहत नो-डिटेंशन पॉलिसी ने कक्षा I से VIII तक के प्राथमिक विद्यालय में कम प्रदर्शन करने वाले बच्चों को दोहराने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र ड्रॉप आउट न हों।
- अब आरटीई में संशोधन हरियाणा सरकार को पाँचवीं और आठवीं कक्षा में नियमित परीक्षा आयोजित करने या राज्य के सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में ऐसी परीक्षा आयोजित करने में विशेषज्ञता रखने वाली किसी अन्य एजेंसी को अधिकृत करने की अनुमति देता है।

नोट :

- संशोधित नियमों में कहा गया है कि यदि कोई बच्चा V (पाँचवीं) कक्षा या VIII (आठवीं) कक्षा में, जैसा भी मामला हो, नियमित परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसे अतिरिक्त निर्देश दिये जाएंगे और परिणाम घोषित होने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर पुन: परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। यदि वह अतिरिक्त निर्देशों और पुन: परीक्षा के अवसर के बाद भी पाँचवीं कक्षा या आठवीं कक्षा की नियमित परीक्षा में विफल रहता है, तो उसे उक्त कक्षा में वापस रखा जाएगा।
- इन कक्षाओं की नियमित परीक्षा पूरी होने के एक महीने के भीतर शैक्षणिक प्राधिकरण या इस तरह की परीक्षा आयोजित करने के लिये अधिकृत एजेंसी द्वारा पाँचवीं और आठवीं कक्षा के पूरा होने का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 2019 में संसद में शिक्षा के अधिकार अधिनियम में संशोधन के पारित होने के बाद कक्षा ट और VIII के लिये नो-डिटेंशन पॉलिसी को निरस्त कर दिया था।

हरियाणा में स्टार्टअप्स को 75% आरक्षण कानून से छूट

चर्चा में क्यों?

- 18 जनवरी, 2022 को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 'हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट, 2020' के तहत नई स्टार्टअप्स और नई आईटी/आईटीईएस कंपनियों को दो साल के लिये छूट दी जाएगी। इसके अलावा निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण देने वाले इस कानून से अल्पकालिक (45 दिन) के कार्यों को भी छूट दी जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जो उद्योग रोज़गार योग्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोज़गार नहीं देते, उन पर 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।
- यह कानून राज्य में निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत नौकरियों को आरक्षित करता है, जो केवल स्थानीय लोगों को 30,000 रुपए प्रति माह से कम वेतन देता है।
- उपमुख्यमंत्री ने अधिनियम में दी गई छूट का विवरण देते हुए कहा कि हरियाणा राज्य रोज़गार स्थानीय उम्मीदवार अधिनियम, 2020 के तहत फसलों की बुवाई, कटाई के अलावा फलों, सब्जियों, चाय की पत्तियों, कॉफी, मछली, जानवरों आदि से संबंधित प्राथमिक कार्यों को भी छूट दी गई है।
- उन्होंने कहा कि घरेलू नौकरों और उन उद्योगों को भी छूट दी गई है, जिनके लिये कुशल श्रमिक उपलब्ध नहीं हैं।
- उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने राज्य में निजी क्षेत्र में हरियाणवी युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण देने वाला यह कानून 15 जनवरी, 2022 की मध्यरात्रि से लागू किया था, जो 10 से अधिक कर्मचारियों वाले उद्योगों में लागू होगा।

हरियाणा, हिमाचल सरकार ने बांध निर्माण के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये

चर्चा में क्यों?

- 21 जनवरी, 2022 को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकारों के बीच 215.35 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से आदिबद्री बांध के निर्माण के लिये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।

प्रमुख बिंदु

- पंचकूला में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटेर और हिमाचल प्रदेश के उनके समकक्ष जयराम ठाकुर के समक्ष दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
- यह बांध हिमाचल प्रदेश में 31.66 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा और हर साल 224.58 हेक्टेयर मीटर पानी का भंडारण करेगा, जिसमें से हिमाचल प्रदेश को 61.88 हेक्टेयर मीटर और हरियाणा को शेष 162 हेक्टेयर मीटर पानी मिलेगा।

नोट :

- आदिबद्री बांध बनने से सरस्वती नदी में लगातार 20 क्यूसेक पानी बहेगा। इससे सरस्वती म् साल भर पानी बहता रहेगा। इस बाँध की चौड़ाई 101.06 मीटर और ऊँचाई 20.5 मीटर होगी।
- खटेर ने कहा कि आदि बद्रीबांध के निर्माण से कई वर्षों से विलुप्त सरस्वती नदी का कायाकल्प होगा। सरस्वती नदी के जीर्णोद्धार से प्राचीन काल से धार्मिक मान्यताओं को भी पुनर्जीवित किया जाएगा, साथ ही इस क्षेत्र को तीर्थस्थल के रूप में भी विकसित किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि सरस्वती नदी पर शोध करने के लिये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक पीठ स्थापित की गई है, इसके अलावा हरियाणा सरस्वती विरासत विकास बोर्ड भी स्थापित किया गया है। हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी के लिये आदि बद्री से कैथल होते हुए घग्गर नदी तक 200 किमी. के क्षेत्र को अधिसूचित किया है।
- खटेर ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ भूजल स्तर को बढ़ाना है। बांध के चालू होने से बरसात के दिनों में अत्यधिक बारिश से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति से भी निपटा जा सकेगा। इसके पास बन रही झील से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
- उन्होंने कहा कि कालका से लेकर कालेसर तक का क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में आदिबद्री, लोहागढ़, कपालमोचन, माता मंत्र देवी समेत कई धार्मिक और पर्यटन स्थल आते हैं। बांध के साथ-साथ झील के विकास से यहाँ कई पर्यटक आएंगे, जिससे दोनों राज्यों को फायदा होगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सहयोग से कई परियोजनाओं पर काम किया जाएगा, जिनमें हथिनीकुंड बैराज पर एक बांध का निर्माण भी शामिल है। इस बांध से बिजली पैदा करने के साथ ही यमुना नदी में साफ पानी का सतत् प्रवाह भी संभव हो सकेगा। इससे फसलों को भी बाढ़ जैसी स्थिति से बचाया जा सकेगा।
- इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आदिबद्री बांध दोनों राज्यों के लिये सिंचाई और पीने के पानी की आवश्यकता को पूरा करेगा। सरस्वती नदी में पानी के बहाव के कारण इस क्षेत्र का विकास धर्म और पर्यटन की दृष्टि से किया जाएगा।
- उन्होंने कहा कि यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के लिये भी बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि पहाड़ी राज्य के लिये पेयजल की आवश्यकता हेतु 3.92 हेक्टेयर मीटर प्रति वर्ष और परियोजना प्रभावित बस्तियों की सिंचाई पानी की मांग के लिये 57.96 हेक्टेयर मीटर पानी निर्धारित किया जाएगा।
- उन्होंने कहा कि परियोजना की पूरी फंडिंग की व्यवस्था हरियाणा सरकार द्वारा की जाएगी। दोनों राज्य सरकारें परियोजना के प्राथमिक उद्देश्यों से समझौता किये बिना, अपने स्वयं के संसाधनों से स्थानीय लोगों के कल्याण और विकास के लिये आवश्यक अन्य बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ पर्यटन परियोजनाओं को तैयार करने हेतु स्वतंत्र होंगी।

इंडियन ऑयल एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल और ग्रीन कॉम्बो लुब्रिकेंट का भारत में पहला ट्रॉयल हरियाणा से हुआ शुरू

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में इंडियन ऑयल द्वारा इंडियन ऑयल एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल और ग्रीन कॉम्बो लुब्रिकेंट का भारत में पहला ट्रायल हरियाणा के बल्लभगढ़ बस अडन्न से शुरू किया गया है। इस ग्रीन डीजल से वाहनों से होने वाले प्रदूषण से राहत मिलेगी, वहीं माइलेज भी 5 प्रतिशत बढ़ जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ स्थित बस अडन्न से इस ट्रायल का शुभारंभ किया। इस ऑयल की खोज फरीदाबाद में इंडियन ऑयल सेंटर ने की है।
- परिवहन मंत्री ने बताया कि एक्स्ट्रा ग्रीन ऑयल के ट्रायल के लिये रोडवेज की 10 बसों का उपयोग किया जाएगा। इनमें निरंतर इस ऑयल का प्रयोग कर सभी पैमानों पर इसकी गुणवत्ता को चेक किया जाएगा।

- इस अवसर पर इंडियन ऑयल के आरडी सेंटर के निदेशक डॉ. एसएसवी रामाकुमार ने बताया कि इंडियन ऑयल के इस ग्रीन कॉम्बो के विभिन्न परीक्षणों में अब तक 5 ओर 7 प्रतिशत और इससे अधिक फ्यूल इकोनॉमी का लाभ हुआ है।
- 40 हज़ार किलोमीटर के ट्रायल के बाद इसे पूरे हरियाणा रोडवेज में लागू किया जाएगा, जिससे हरियाणा रोडवेज को सालाना लगभग 40 करोड़ रुपए का फायदा होगा।
- इस एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल और ग्रीन कॉम्बो लुब्रिकेंट से प्रदूषण में कमी आएगी और गाड़ियों की माइलेज भी बढ़ेगी। इससे लगभग 1000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण में लाभ मिलेगा।

राज्य सूचना आयोग के भवन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर होगा

चर्चा में क्यों ?

- 23 जनवरी, 2022 को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटेर ने पंचकूला में बनने वाले राज्य सूचना आयोग के भवन का शिलान्यास किया और इस भवन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- पंचकूला के सेक्टर-3 में 36.49 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनने वाले इस राज्य सूचना आयोग भवन का निर्माण दो साल में पूरा होने का अनुमान है।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटेर ने बताया कि देश भर में चल रहे भारत की आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के तहत सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर हरियाणा में 75 स्थानों पर 'पराक्रम दिवस' का आयोजन किया गया है।
- राज्य भर में जनभागीदारी के साथ 'हरियाणा बोलेगा जय हिंद बोस' के नारे के साथ लगभग 495 कार्यक्रम आयोजित किये गए।
- मुख्यमंत्री ने 'पराक्रम दिवस' के अवसर पर चंडीगढ़ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर पार्क में स्थापित उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया।

हरियाणा में हर साल एक हज़ार युवाओं को दिया जाएगा साहसिक-खेल प्रशिक्षण

चर्चा में क्यों ?

- 23 जनवरी, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटेर ने घोषणा की कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के 1,000 युवाओं को हर साल साहसिक खेलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उन्हें रोज़गार मिल सके।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने यह घोषणा हरियाणा के खेल एवं युवा मामले विभाग द्वारा आयोजित 'मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब' के तहत 'युवा उद्यमी' नामक प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में युवाओं को संबोधित करते हुए की।
- मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटेर ने कहा कि इसके अलावा कालेसर, धोसी, अरावली और मेवात की पहाड़ियों में एडवेंचर-स्पोर्ट्स शुरू किए जाएंगे, जहाँ हर साल तीन से पाँच 'एडवेंचर-स्पोर्ट्स कैंप' आयोजित किये जाएंगे। उक्त शिविरों में प्रशिक्षण पर प्रतिवर्ष दो करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि ऐसे शिविर मोरनी, पंचकूला में आयोजित किये जा रहे हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मोरनी क्षेत्र के 16 से 29 वर्ष के बीच के युवाओं को 'एडवेंचर-स्पोर्ट्स एंड होम-स्टे' से संबंधित उद्यमिता के बारे में प्रशिक्षण दिया गया।
- मुख्यमंत्री ने युवाओं को 'नौकरी तलाशने वाले' के बजाय 'नौकरी देने वाले' बनने का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय रोज़गार मेलों का आयोजन करके गरीब से गरीब व्यक्ति के उत्थान का प्रयास किया जाएगा।
- राज्य गरीबों को ऋण की सुविधा और स्वरोज़गार के विभिन्न तरीकों के बारे में जागरूक कर रहा है, जिसमें पोल्ट्री फार्म, मछली पालन, पशुपालन आदि शुरू करना शामिल है ताकि उनकी आय को बढ़ाया जा सके।

हरियाणा के 2 बच्चे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

- 24 जनवरी, 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक वर्चुअल समारोह में देश के 61 बच्चों को वर्ष 2021 एवं 2022 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया, जिनमें 2 बच्चे हरियाणा के हैं।

प्रमुख बिंदु

- इस वर्ष के इन पुरस्कार विजेताओं में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 15 लड़के और 14 लड़कियाँ शामिल हैं। ये बच्चे देश के सभी क्षेत्रों से नवाचार (7), सामाजिक सेवा (4), शैक्षिक (1), खेल (8), कला और संस्कृति (6) तथा वीरता (3) श्रेणियों में अपनी असाधारण उपलब्धियों के लिये चुने गए हैं।
- इसी प्रकार वर्ष 2021 के पुरस्कार विजेताओं में 21 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 32 बच्चे नवाचार (9), कला एवं संस्कृति (7), खेल (7), शैक्षिक (5), वीरता (3) तथा सामाजिक सेवा (1) श्रेणियों में चुने गए हैं।
- पीएमआरबीपी पुरस्कार विजेता हर साल गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेते हैं। पीएमआरबीपी के प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, एक लाख रुपए का नकद पुरस्कार और एक प्रमाण-पत्र दिया जाता है।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार- 2022 से सम्मानित हरियाणा के दो बच्चे हैं- तनिष सेठी (नवाचार) एवं आकर्ष कौशल (सामाजिक सेवा)।
- पीएमआरबीपी 2021 और 2022 के पुरस्कार विजेता अपने माता-पिता और अपने-अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट के साथ संबंधित जिला मुख्यालय से इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
- प्रधानमंत्री ने समारोह के दौरान राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित ब्लॉकचेन संचालित तकनीक का उपयोग करके पीएमआरबीपी 2021 और 2022 के 61 विजेताओं को डिजिटल प्रमाण-पत्र प्रदान किये।

हरियाणा के 5 व्यक्ति पद्म पुरस्कारों के लिये चयनित

चर्चा में क्यों ?

- 25 जनवरी, 2022 को भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार 2022 की घोषणा की। इसके अनुसार हरियाणा से खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल, सोशल वर्क में ओमप्रकाश गांधी, साइंस एंड इंजीनियरिंग में मोती लाल मदान, साहित्य एवं शिक्षा में राघवेंद्र तंवर को पद्मश्री पुरस्कार के लिये चयनित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि ट्रैक और फील्ड एथलीट प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में 87.58 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। इस स्वर्णिम उपलब्धि को हासिल करके वे ट्रैक और फील्ड स्पर्धा में भारत की तरफ से ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट बने हैं।
- इसी प्रकार, सुमित अंतिल ने टोक्यो 2020 पैरालंपिक में F64 पुरुषों की जेवलिन थ्रो में 68.55 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता।
- गुर्जर कन्या विद्या मंदिर के संस्थापक ओमप्रकाश पोसवाल गांधी अपनी विनम्रता, शालीनता, व्यवहार कुशलता और लोगों को संगठित करने की क्षमता के कारण अपने संकल्प को मूर्तरूप देकर 7 अप्रैल, 1987 को गुर्जर कन्या विद्या मंदिर का शुभारंभ किया। अपनी स्थापना से लेकर आज तक विद्यालय उन्हीं के प्रबंधन और मार्गदर्शन में प्रगति के पथ पर अग्रसर है।
- बीवीएससी और एएच व एमएससी (पंजाब विश्वविद्यालय) में गोल्ड मेडलिस्ट, पीएचडी (यूएमसी, यूएसए), डीएससी से सम्मानित मोतीलाल मदान को साइंस एंड इंजीनियरिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिये पद्मश्री पुरस्कार के लिये चुना गया है।

- ये विभिन्न शिक्षण संस्थानों के कुलपति भी रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संदर्भित पत्रिकाओं में इनके 432 शोध लेख और नीति पत्र प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें 226 मूल शोध पत्र शामिल हैं।
- साहित्य एवं शिक्षा में राघवेंद्र तंवर को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। इतिहास में प्रथम स्थान व सामाजिक विज्ञान संकाय में सर्वाधिक अंक प्रतिशत हेतु सम्मानित, यू.जी.सी. के राष्ट्रीय फैलो, अध्यक्ष, पंजाब इतिहास कॉन्ग्रेस (मॉडर्न 2001) तथा प्रथम अध्यक्ष, भारतीय इतिहास कॉन्ग्रेस (समकालिक 2008) प्रो. तंवर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता शैक्षणिक, अधिष्ठाता सामाजिक विज्ञान संकाय एवं कुलसचिव के पदों पर आसीन रहे हैं।
- उनकी पुस्तक 'पॉलिटिक्स ऑफ शेयरिंग पावर : द पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी 1923-1947' को विभाजन के पूर्व पंजाब में विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था पर एक महत्त्वपूर्ण एवं सर्वस्वीकार्य शोध के रूप में मान्यता दी जाती है।

हरियाणा पुलिस के 14 अधिकारी पुलिस पदक से अलंकृत

चर्चा में क्यों?

- 25 जनवरी, 2022 को हरियाणा पुलिस के 14 पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिये चुना गया है।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस महानिरीक्षक करनाल रेंज, ममता सिंह और सीआईडी पंचकूला के पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र वत्स को विशिष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है।
- 12 अन्य पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है। इनमें धर्मबीर सिंह, कमांडेंट द्वितीय आईआरबी भोंडसी गुरुग्राम, अनिल कुमार डीएसपी नारायणगढ़, शीतल सिंह डीएसपी आरटीसी भोंडसी गुरुग्राम, मनीष सहगल डीएसपी सीआईडी फरीदाबाद, सुनीता रानी इंस्पेक्टर आरटीसी भोंडसी गुरुग्राम, जनक राज उप-निरीक्षक हिसार, सुख राम सिंह ईएसआई पंचकूला, उमेश कुमार ईएसआई फरीदाबाद, सीमा ईएसआई टेलीकॉम पंचकूला, राम गोपाल एएसआई जीआरपी कुरुक्षेत्र, विनोद कुमार एएसआई सीआईडी, पंचकूला और राजेश कुमार एएसआई पुलिस मुख्यालय पंचकूला शामिल हैं।
- पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) हरियाणा, प्रशांत कुमार अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर मिली इस उपलब्धि से पुलिस पदक से अलंकृत होने वालों के साथ-साथ राज्य पुलिस बल के अन्य अधिकारियों व जवानों का भी मनोबल बढ़ेगा।

गुरुग्राम में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन

चर्चा में क्यों?

- 28 जनवरी, 2022 को इलेक्ट्रिक वाहन के लिये राष्ट्रीय राजमार्ग (NHEV) ने हरियाणा के गुरुग्राम में भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस स्मार्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन में 100 चार्जिंग पॉइंट हैं।
- इससे पहले, देश का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन नवी मुंबई में स्थित था।
- यह चार्जिंग स्टेशन Alektrify द्वारा स्थापित और संचालित किया गया है, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पायलट प्रोग्राम के तहत जयपुर-दिल्ली-आगरा ई-हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिये एनएचईवी की आधिकारिक कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन पार्टनर कंपनी है।

उन्नति ने जीता ओडिशा ओपन

चर्चा में क्यों ?

- 30 जनवरी, 2022 को हरियाणा की 14 वर्षीय उन्नति हुडन्न ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं।

प्रमुख बिंदु

- उन्नति ने फाइनल में स्मित तोशनीवाल पर 21-18 तथा 21-11 से जीत दर्ज की, जबकि सेमीफाइनल में इन्होंने मालविका बंसोड़ को पराजित किया था।
- उल्लेखनीय है कि ओडिशा ओपन, 2022 एक बीडब्ल्यूएफ सुपर 100 टूर्नामेंट है, जो कटक जिले के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में 25 से 30 जनवरी, 2022 तक आयोजित किया गया।
- इसका आयोजन बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की मंजूरी के साथ किया गया।
- इस टूर्नामेंट में कुल 75,000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार पूल था।

The Vision

नोट :